मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय उच्चाधिकारियों, जिला प्रभारी सचिवों, संभागीय आयुक्त व कलैक्टरों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को पानी-बिजली सप्लाई की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये तथा अधिकारियों के साथ प्रदेश में वॉटर हार्वेस्टिंग एवं आम जन शिकायत निवारण सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जिला प्रभारी सचिवों, कलैक्टर्स और संभागीय आयुक्तों की बैठक ली

बैठक मुख्यतया भारी हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के मुद्दे पर बुलाई गई थी

- **मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को हर गांव-कस्बे व शहर में बिजली, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।**
- **मुख्यमंत्री ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।**

जयपुर, 31 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय उच्चाधिकारियों, जिला प्रभारी सचिवों, संभागीय आयुक्त एवं कलैक्टर्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि, भीषण गर्मी के दौर में आमजन को बिजली और पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। जिस भी दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है, एक्सचेंज से खरीद कर राज्य सरकार आमजन को उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि खराब ट्रांसफार्मर को रिपेयर या रिप्लेस कर ट्रिपिंग की समस्या का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही, कमी होने पर जिलों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आपूर्ति भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रभारी जिला सचिव अपने दौरे के दौरान औपचारिक समीक्षा बैठकों तक ही सीमित ना रहें, अपितु फील्ड में औचक निरीक्षण कर परिवादों एवं शिकायतों का वास्तविक समाधान सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड विज़िट में बिजली, पानी या एजेण्डा बिन्दुओं के साथ-साथ नए एवं पुराने सभी कार्यों और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रभारी जिला सचिव जलापूर्ति से संबधित परियोजनाओं व कार्यों की सघन मॉनिटरिंग करें और प्रत्येक जिले में ट्यूबवेल की समीक्षा कर अधिकारियों को ट्यूबवेल सूखने के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार ने गर्मी के मौसम में बिजली की मांग 3 हजार 777 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बावजूद भी आमजन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई है।

शर्मा ने आमजन से बिजली और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की और अधिकारियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जन जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मानसून से पहले जल संग्रहण एवं संचयन के ढांचों (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्धस्तर पर कार्य किए जाएं। साथ ही, परंपरागत पेयजल एवं जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने और भू-जल स्तर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शर्मा ने कहा कि, हीटवेव एवं मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो। उन्होंने अस्पतालों में मरीजों को राहत देने के लिए पर्याप्त संख्या में कूलर, एसी, वाटर कूलर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि, गौशालाओं में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए समय पर अनुदान जारी किया जाए।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि, चुनाव आचार संहिता में पहले सभी काम ठप पड जाया करते थे, लेकिन इस बार सरकार ने भर्ती प्रक्रिया से लेकर टेंडर, खरीद आदि के 141 मामलों में भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर यह सुनिश्चित किया कि जरूरी कार्य बाधित न हों। उन्होंने कहा कि, राजकीय अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थानांतरण नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और शीघ्र ही इसका प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री के समक्ष किया जाएगा। गत 15 दिन में ही दो हजार नई नियुक्तियां दी गई हैं।

क्या प्रशासन गुंजल की पत्नी की फर्म के काम को गैर प्रशासनिक तरीके से रोक रहा है?

- **हाईकोर्ट ने इस मामले में गुंजल की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, सरकार जय कंवर गुंजल की फर्म को सुनवाई की अगली तारीख तक सुचारू रूप से काम करने दे।**
- **इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने कहा कि, जय कंवर गुंजल की फर्म, बाल बालाजी क्रशर्स को सरकार द्वारा गठित समिति एक अवर्णित भूमि का सर्वे करने के नाम पर काम करने से रोक रही है, जबकि किसी भी विभाग ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है, जिससे फर्म का काम बंद करना पड़े।**

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 31 मई। लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की पत्नी जय कंवर गुंजल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि, राज्य सरकार के कई विभाग उनकी फर्म, बाल बालाजी क्रशर्स के क्रशर्स को चलाने नहीं दे रहे हैं, जबकि किसी भी विभाग ने उनके क्रशर का कार्य रोकने के लिये आदेश पारित नहीं किये हैं।

हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि, वह बाल बालाजी क्रशर्स को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी कार्य से अवरूद्ध ना करें। न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश जय कंवर गुंजल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये। इस मामले की अगली तारीख जुलाई में तय की गई है।

इस मामले में यचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी.माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता विवेक यादव, वर्णित जैन और फलक माथुर पैरवी के लिये पेश हुए।

इस मामले की जिरह के दौरान आर.बी.माथुर ने अदालत को बताया कि, राज्य सरकार ने कई विभागों के अफसरों की एक टीम गठित की थी जिसे एक अवर्णित भूमि के क्षेत्र का सर्वे करना था, परंतु इस कमेटी के अधिकारी सर्वे की आड़ में बाल बालाजी क्रशर्स को कार्य करने से अवरूद्ध कर रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि, राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है जिससे बाल बालाजी क्रशर्स को काम करने से रोका गया हो।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, कोटा जिले के कलेक्टर, एस.पी. कोटा, कोटा डवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव, यू.आई.टी. कोटा के सचिव तथा अन्य अफसरों से जवाब तलब किया है। अदालत ने आदेश दिये हैं कि, नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जायें और पावती रसीद प्राप्त की जाये। अदालत ने कहा कि, नोटिस की पूर्ति होने के बाद ही मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

नीरव,माल्या व मेहुल चोकसी को लेकर ई.डी. की कोर्ट में जमकर खिंचाई हुई

- **मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि, ये सभी लोग ई.डी. की नाकामी की वजह से देश छोड़कर भाग गये।**

मुंबई, 31 मई (वार्ता) महाराष्ट्र में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी को पकड़ने में विफलता के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की खिंचाई की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने चार्टर्ड अकाउंट व्योमेश शाह की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति को खत्म करने की मांग की थी। शाह पर गरवारे इंडस्ट्रीज के निहाल गरवारे के लिए धन शोधन का आरोप है, जिसे पिछले साल बीकेसी में एक संपत्ति सौदे के माध्यम से जेएंडके बैंक को एक सौ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शाह ने जमानत आदेश में संशोधन की मांग करते हुए विशेष अदालत का रुख किया था।

गर्मी से पुलिस कांस्टेबल की मौत

- **धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल भूपेन्द्र की शुक्रवार दोपहर गर्मी की वजह से तबियत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।**

धौलपुर, 31 मई (निसं)। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र की अंडवा पुरैनी चौकी पर तैनात एक कांस्टेबल की शुक्रवार दोपहर को गर्मी की वजह से अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे साथी पुलिसकर्मी जिला अस्पताल धौलपुर लेकर गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

जानकारी के अनुसार, चंबल के बीहड़ों में स्थित अंडवा पुरैनी चौकी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल भूपेंद्र (42) पुत्र पूरन, निवासी टुहिया भरतपुर रोजाना की तरह शुक्रवार को भी ड्यूटी पर तैनात था। दोपहर में अचानक भूपेंद्र की तबीयत बिगड़ गई। उसके साथी कांस्टेबल हरेंद्र ने थाने पर कांस्टेबल भूपेंद्र की तबीयत खराब होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर कांस्टेबल को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन, रास्तेमें ही उसकी मौत हो गई।

प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि, कांस्टेबल भूपेंद्र की मौत भीषण गर्मी के कारण हुई है। कांस्टेबल की मौत की सूचना से धौलपुर जिले के पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई तथा परिजनों और रिश्तेदारों में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार मृतक कांस्टेबल वर्ष 2008 में भीलवाड़ा जिले में पुलिस में भर्ती हुआ था। जिसके बाद साल 2017 में उसका ट्रांसफर धौलपुर जिले में हो गया था।

राजनीतिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने की संभावना जताई। विपक्ष को चन्द्रबाबू नायडू के भी एन.डी.ए. छोड़ कर इंडिया गठबंधन में आने की उम्मीद है।

गंगोत्री हाईवे पर चट्टानें गिरीं, एक की मौत कई यात्री घायल

नैनिताल, 31 मई। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर चट्टान के गिरने से एक यात्री की मौत हो गई है। हादसे में पांच अन्य यात्री भी घायल हैं। हादसे के बाद यात्रा को रोका गया है। घटना के बाद राहत व बचाव का कार्य जारी है। मलबे में कई गाड़ियां भी दबीं हैं।

शुक्रवार दोपहर को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने की सूचना मिली थी। हादसे में कई गाड़ियों समेत कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई गई थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत व बचाव कार्य के लिए रवाना हो गईं।

पुलिस-प्रशासन की टीम ने तुरंत ही मौके पर रैस्कयू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

प्रशासन की ओर से हाईवे पर गाड़ियों को रोका गया है। बताया कि, हाईवे पूरी तरह से सुरक्षित होने पर ही यात्रियों को रवाना किया जाएगा। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं हैं। बताया गया है कि हादसे वाली जगह पर इन दिनों सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क की बाहरी तरफ के पुश्ता का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

देश की जी.डी.पी. आंकड़ों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सार्वजनिक निवेश में, तकरीबन 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं, जो कि एक मजबूत रुझान है। यह राजस्व के शानदार कलैक्शन सहित कई कारकों से ही संभव हो सका है। जी.एस.टी. प्राप्तियां माह दर माह 1 लाख करोड़ रुपयों से अधिक रही हैं, जिसकी वजह से सार्वजनिक वित्त एक सुखद स्थिति में आ गया है। लागत वृद्धिके बावजूद वित्तीय घाटा 5.6 प्रतिशत पर बना हुआ है।

सरकार के वित्त को रिज़र्व बैंक से भी मदद मिली है। रिज़र्व बैंक ने केन्द्र सरकार को अभूतपूर्व उच्च लाभांश हस्तांतरित किए हैं। उसने केन्द्र सरकार को 2011 लाख करोड़ ट्रांसफर किए हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अर्जित बड़ी मात्रा के आधिन्य ने भी शायद केन्द्र सरकार की व्यय योजनाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये योजनाएं इन सबके बीच एक विवेकशील वित्तीय मानदण्ड में रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक पूर्णरुपेण निजी उपभोग व्यय पर निर्भर रहती आई है। कई अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार की एक तरफा निर्भरता को लेकर चेतावनी दी है। जब अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ उपभोक्ता मांग ही करती है, तब मांग में अचानक आने वाली कोई कमी आर्थिक विकास की संभावनाओं को कुल मिलाकर फीका कर देती है।

नवीनतम आंकड़े संकेत देते हैं कि घरेलू उपभोग लगातार मजबूत रहा है। उच्च आवृत्ति वाले कुछ आंकड़े ऑटो सेल्स हाउसिंग लोन्स, फ्यूल कंज़म्पशन जैसे कुछ विशिष्ट सैगमैन्ट्स में आर्थिक विकास की तेज गति का संकेत देते हैं। इस वर्ष सामान्य मानसून की भविष्यवाणी के बावजूद आर्थिक मजबूती के वास्तविक सैगमैन्ट "मांग" में थोड़ी कमी है।

समग्र अनुकूल पृष्ठभूमि को देखते हुए, अगली सरकार की कुछ प्राथमिकताएं हैं। आर्थिक नीति संचालकों को जोर इस पर होना चाहिए कि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने के लिए अपने प्रचुर संसाधनों का उपयोग किया जाए। यदि इनकी सक्रियता बरकरार रहती है तो ये एक नियत समय में प्राइवेट सैक्टर के बड़े निवेशों तक पहुंच जाएंगे।

निजी निवेश तब आते हैं, जब उनकी क्षमता का उपयोग अधिक हो और उत्तरोत्तर वृद्धि के ट्रैण्ड्स दिख रहे हों। कुछ बिज़नैस कॉन्फिडैंस सर्वे व अन्य संकेतकों से पता चलता है कि बड़े निजी निवेशों के लिए मनोभाव सकारात्मक बन रहे हैं। निजी सैक्टर के निवेशों में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।

वास्तव में, भारत में भारतीय निजी निवेशकों के साथ ही प्राइवेट सैक्टर की कुछ बड़ी कम्पनियों का भी आना तय है। केन्द्र सरकार की इन्सैन्टिव स्कीम्स को देखते हुए अधिकाधिक निवेशक भारत को लेकर प्रसन्न मुद्रा में हैं। कम्प्यूटर चिप मेकिंग और सैमीकन्डक्टर इण्डस्ट्री सहित कुछ सैक्टर्स में महत्वपूर्ण नई शुरूआत की उम्मीद है।

इन ट्रैण्ड्स को देखते हुए कोई भी यह सहज भविष्यवाणी कर सकता है कि अर्थव्यवस्था की गति मजबूत बनी रहेगी और वित्तीय बाज़ार थोड़ी तेजी दर्शा सकते हैं।

'किसी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं हुआ'

नई दिल्ली, 31 मई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोन डिफाल्टर्स के साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जा रही है और ईडी ने अब तक 64,920 करोड़ की संपत्ति अटैच कीहै। उन्होंने कहा कि इस तरह के 1105 डिफाल्टर अब भी जांच के दायरे में हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में किसी भी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, विपक्ष झूठ बोनलने और अफवाह फैलाने का आदी हो गया है। विपक्ष के लोगों को लोन वेवर और राइटऑफ में भी फर्क समझ नहीं आता है। उन्होंने कहा, आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक राइटऑफ के बाद बैंक सक्रकिय रूप से बैड लोन की रिकवरी में जुट जाते हैं। किसी भी उद्योगपति का कोई भी कर्ज मोदी सरकार में माफ नहीं किया गया है। वहीं बैंकों ने बैड लोन से 10 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी की है।

'बहुमंजिला निर्माण पर "यथास्थिति" सिर्फ गांधी नगर इलाके में ही है'

- **हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, न्यायाधीशों के बंगलों के सामने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर "यथास्थिति" बनाए रखने का आदेश सिर्फ गांधी नगर इलाके के लिए ही है, अन्य क्षेत्रों पर यह प्रभावी नहीं होगा।**

जयपुर, 31 मई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस (सी.जे.) सहित अन्य न्यायाधीशों के बंगलों के सामने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के मामले में स्पष्ट किया है कि, बहुमंजिला निर्माण पर यथास्थिति केवल गांधी नगर इलाके में ही है और शहर की अन्य जगहों पर नहीं है। ऐसे में एकलपीठ का 15 मई का आदेश केवल गांधी नगर इलाके में ही लागू होगा।

सी.जे. एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में प्रार्थी मनीषा मालिनी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता संजय जोशी ने खंडपीठ को बताया कि, एकलपीठ ने 15 मई को गांधी नगर सहित अन्य संबंधित जगहों पर बहुमंजिला निर्माण पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। यह प्रसंज्ञान 2019 में दिए एक निर्णय के आधार पर लिया था और इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग चल रही है। ऐसे में एकलपीठ को 2019 के निर्णय के आधार पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था।

अधिवक्ता जोशी ने कहा कि, एकलपीठ ने यथास्थिति किस जगह के बारे में दी है वह भी अपने आदेश में स्पष्ट नहीं किया है और ना ही बहुमंजिला इमारत की जानकारी दी है। वहीं प्रार्थिया को ई.डब्ल्यु.एस. वर्ग में एक फ्लैट आवंटित हुआ है, लेकिन बिल्डर हाईकोर्ट के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान आदेश का हवाला देते हुए उसे कब्जा नहीं दे रहा है। इसलिए एकलपीठ के आदेश को स्पष्ट करवाया जाए।

खंडपीठ ने प्रार्थी पक्ष की दलीलों से सहमत होकर स्पष्ट किया कि बहुमंजिला निर्माण पर यथास्थिति केवल गांधीनगर इलाके में ही है और अन्य जगह पर नहीं है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 15 मई को शहर के गांधीनगर इलाके में हाईकोर्ट के सी.जे. सहित अन्य न्यायाधीशों के बंगलों के सामने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था और गांधीनगर सहित अन्य संबंधित स्थानों पर बहुमंजिला निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। एकलपीठ ने इन बहुमंजिला भवनों के निर्माण की मंजूरी देने पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि, इनसे आम लोगों के लिए बिजली-पानी व रोशनी पर संकट पैदा होगा। उन्होंने सी.जे. सहित अन्य जजों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जाहिर की थी।

एग्ज़िट पोल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाएगी उस समय इंडिया नैशनल डवलपमेंटल इंक्लुसिव एलांयस (इंडिया) निर्णायक जनादेश की ओर अग्रसर हो रहा होगा।

अंतिम चरण के चुनाव से एक दिन पहले शुक्रवार को यहां ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में आयोजित संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार, जयराम रमेश, मीडिया व पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा एवं सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफार्म्स की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि, देश की जनता से मुद्दों पर आधारित प्रचार अभियान से पार्टी को पहचान लिया है, जो राजनीति की गरिमा की सीमा का किसी भी तरह उल्लंघन नहीं करती है।

किशोरियों की बिक्री के मुद्दे पर राजस्थान को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

नयी दिल्ली, 31 मई (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान की किशोरियों को दूसरे राज्यों में बेचने की शिकायतों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

आयोग ने राज्य सरकार को बालिकाओं की तस्करी और वेश्यावृत्ति के कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिये राज्य स्तरीय मानव तस्करी विरोधी नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उसे जिला मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (डीएएचटीयू) के सहयोग के साथ मिलकर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिये काम करने को कहा है।

आयोग की शुक्रवार को जारी विज्ञिप्त के अनुसार, उसने राज्य सरकार द्वारा हाल की कुछ ऐसी घटनाओं में मामला दर्ज किये जाने की बात स्वीकार की है लेकिन कहा है कि ऐसा लगता है कि किशोरियों की तस्करी की घटनाएं जारी हैं। आयोग ने मानव तस्करी रोकने और पीड़ितों के पुनर्वास जैसे कार्यों के लिये केन्द्रीय गृह मंत्रालय की व्यापक योजना के तहत गठित की जाने वाली डीएएचटीयू को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजें हैं। आयोग ने उनसे इस संबंध में अब तक की गयी कार्रवाई का आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा है।

आयोग के संज्ञान में राजस्थान में किशोरियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों तथा विदेशों में शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न के लिये भेजे जाने के मामले आये थे।

सट्टा बाजार भाजपा को 306...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह संशोधन मुख्य रूप से इस संदेह से उत्पन्न होता है कि भाजपा का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार जैसे राज्यों में हल्का रहा है। भविष्यवाणियों का संकेत है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में स्वघोषित दावों से कम सीटें मिल सकती है। वर्ष 2019 की 62 सीटों की तुलना में उसे इस बार के चुनावों में 54 सीटें मिलने का अनुमान है। यद्यपि, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आश्चर्यजनक बढ़त हासिल की है। कुल मिलाकर, सट्टा बाजार की भविष्यवाणी यह है कि भाजपा के नेतृत्व वाला एन.डी.ए. गठबंधन को 306 सीटें मिलेंगी, साथ कांग्रेस को 55 से 65 सीटों के बीच सीटें प्राप्त होते बताया है।

महाराष्ट्र में सट्टा बाज़ार सत्तारूढ़ महायुति को 48 में से 30 सीटें मिलना बता रहा है जो गठबंधन के स्वयं की अपेक्षाओं से थोड़ा सा कम है। विशेष रूप से महाविकास अघाड़ी में शिव सेना सबसे अधिक सीटें जीत सकती है।

मजेदार बात यह है कि राजस्थान में फलौदी का सट्टा बाज़ार भी मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ होता देख रहा है। चुनावों के द्वितीय चरण के बार प्रारंभिक अनुमान में भाजपा के लिए 270 से 280 सीटों का दावा किया है और कांग्रेस को 70-80 सीटों के बीच का अनुमान बताया है। उतार-चढ़ाव के बावजूद, फलौदी सट्टा बाज़ार के अनुमान के अनुसार भाजपा को 300 से कम सीटें प्राप्त होंगी जबकि इंडिया ब्लॉक के लिए अनुमानित सीटें 80 से 95 के बीच दर्शा रहा है।

फलौदी सट्टा बाज़ार जोधपुर से लगभग 160 कि.मी. दूर स्थित है। फलौदी बाज़ार का महत्व यहाँ के खास सट्टा बाज़ार की वजह से है। यह बाज़ार किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए विख्यात है जिसमें चुनावों के परिणाम भी शामिल हैं।

फलौदी सट्टा बाज़ार दलालों के माध्यम से कार्य करता है जो मतदाता के मूड का विश्लेषण करते हैं तथा भिन्न-भिन्न शर्तों के लिए चुनावों के रूझान के अनुसार भाव तय करते हैं।

इस बाजार की काल्पनिक सटीकता का श्रेय देश भर में व्यापक रूप से फैले मुखबिरों के नेटवर्क को दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा को कुल 80 सीटों में से 55 से 65 सीटें जीतने की उम्मीद है, पर फलौदी सट्टा बाज़ार इसमें कमी कर रहा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों के बावजूद भाजपा को संभावित राजनीतिक लाभ मिलने की अपेक्षा नहीं है।

उत्तर प्रदेश से आगे इसके सट्टेबाजों की निगाहें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं बिहार जैसे राज्यों पर भी है। भाजपा पिछले लोकसभा चुनावों में 42 में से 16 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत चुकी है, यहां इसे आगे लाभ मिलने का अनुमान है। बिहार व महाराष्ट्र में राजनीतिक दृश्य जटिल बना हुआ है। बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया है तथा महाराष्ट्र में शिव सेना व एन.सी.पी. के बीच चल रही कलह के चलते चुनावी दृश्य जटिल बना हुआ है।

कर्नाटक पुलिस ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि, कौनसे मोबाइल फोन से सबसे पहले वीडियो बनाए गए थे और फिर वे इसके बारे में प्रज्वल रैवन्ना से सवाल पूछे जाएंगे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक डिवाइस को नष्ट कर दिया गया है और अगर जाँचकर्ता उसको ढूढ़ने में असफल रहते हैं तो जनता दल (एस) के सांसद के विरूद्ध "सबूत के साथ छेड़छाड़" का आरोप भी लगाया जायेगा। प्रज्वल रैवन्ना जो कि, एन.डी.ए. प्रत्याशी के रूप में हासन लोकसभा चुनाव क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने अप्रेल में देश छोड़ दिया था जब वो वीडियो क्लिप्स जिसमें कथित रूप से उनके द्वारा कई महिलाओं को यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया था, पूरे कर्नाटक में चर्चा का विषय बन गए थे।

26 अप्रेल को, लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में, हासन में मतदान हुआ था। इसी बीच एस.आई.टी. ने प्रज्वल की माँ भवानी रैवन्ना को भी एक अपहरण के मामले में 1 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। अभी तक प्रज्वल रैवन्ना के खिलाफ रेप के तीन मामले दर्ज हो चुके हैं।

प्रज्वल के वकील अरूण जी. ने मीडिया के लोगों को बताया कि, "कल उसे इमिग्रेशन सैंटर पर प्रॉसीजर के मुताबिक रोका गया था। वो जाँच-पड़ताल में सहयोग करने के लिए आया है और वह यही कह रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से प्रार्थना की है कि, कृपया मीडिया ट्रायल ना करें।"

'फैसले लिखने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली लम्बी छुट्टियों की आलोचना की और कहा कि, इतने केस पैंडिंग हैं ऐसे में इतने लंबे अवकाश की क्या जरूरत है?

सान्याल के आलेख पर कानून विशेषज्ञों व प्रोफैशनल्स में तीखी बहस छिड़ गई। मौजूदा व्यवस्था के समर्थकों ने न्यायिक समर्पण पर जोर दिया। सान्याल ने संरचनात्मक बदलाव पर जोर दिया ताकि लंबित केसों के ढेर की समस्या का समाधान किया जा सके।

बार काउन्सिल ऑफ तमिलनाडू एण्ड पुडुचेरी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू ने मौजूदा व्यवस्था की वकालत की और कहा कि, जज छुट्टियों का उपयोग फैसले लिखने में करते हैं।

बार काउन्सिल व पांचू की प्रतिक्रिया के जवाब में सान्याल ने कहा कि औरों की तरह जज भी छुट्टी के अधिकारी हैं। पर इसके लिए पूरे लीगल सिस्टम क अवरूद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

अर्थशास्त्री शामिका रवि ने सान्याल का समर्थन किया व कहा जजों के कार्य दिवस बढ़ाने लंबित केसों का ढेर कम हो जाएगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908